इंडिया टीवी .in
www.indiatv.in

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या-क्या है?

1. वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपये हो गया
2. शहरी आर्थिक क्षेत्रों (सीपीएसई) की महत्वपूर्ण अचल संपत्ति संपत्तियों के पुनर्चक्रण में तेजी लाने के लिए समर्पित आरईआईटी की स्थापना
3. उधारदाताओं को विवेकपूर्ण ढंग से निर्धारित आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी कोष
4. प्रत्येक शहरी आर्थिक क्षेत्र (सीईआर) के लिए 5 वर्षों में 5000 करोड़ रुपये का आवंटन
5. तटीय माल ढुलाई प्रोत्साहन योजना से 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय जहाजरानी की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 12% हो जाएगी
6. संचालन में सहायता प्रदान करने के लिए सीप्लेन वीजीएफ योजना शुरू की जाएगी
7. पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे
8. अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग (उत्तर पश्चिम)
9. पर्यावरण के अनुकूल यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल गलियारे 'विकास कनेक्टर' के रूप में
10. आवश्यक मानव संसाधन के विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे